ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

हरे रंग की हुई अंटार्कटिका की सफेद बर्फ

रविवारीय, 24 - 30 मई 2020 वर्ष- एक, अंक-42, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 2 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

राज्य सरकार लोगों में इम्युनिटी बुस्टींग का कर रही कार्य

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार मुख्य रूप से लोगों के इम्युनिटी बुस्टींग पर ध्यान दे रही है। सरकार लोगों को क्वारंटाईन सेंटर में रखकर रोजाना ऐसे पौष्टिक आहार दे रही है जिससे लोगों के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिये जिला आयुष कार्यालय गुमला ने आयुर्वेदिक इम्युनिटी बूस्टर काढ़ा तैयार किया गया है। जो कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम में सहायक रहेगी। इस काढ़े का रोजाना 2 से 3 बार सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढती है। मिश्रण में इस्तेमाल की गई सामग्रियां जैसे तुलसी, दालचीनी, सौंठ एवं गोलमिर्च कोरोना वायरस के साथ-साथ खांसी, सर्दी जैसे कई रोगों से हमें बचाता है। आने वाले दिनों में यह आयुर्वेदिक काढ़ा जिले के तमाम कोविड केयर सेंटर एवं क्वारनटाईन केंद्रों में रहने वाले श्रमिक बंधुओं व अन्य लोगों तथा जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में भी उपलब्ध कराया जाएगा।

देश में कोरोना से इतनी कम मौतें किसी सरकारी प्रयास से नहीं बल्कि भारतीयों की रोग से लड़ने की क्षमता के कारण है यानि

दैवीय कृपा से बचा है भारत

मुख्य संवाददाता

रांची : भारत में कोरोना मरीजों की संख्या डेढ लाख पहुंचने को है। हाल के कुछ दिनों से प्रतिदिन पांच छह हजार मरीजों की संख्या में वृद्धी हो रही है। मुंबई विश्व में कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में मास्को के बाद दुसरे स्थान पर बना हुआ है। दिल्ली, गुजरात में कोरोना नियंत्रित नहीं हो रहा है। अब जब मजदूरों कामगारों को उनके गांव और गृहजिलों में जाने की अनुमति मिल गयी है तो ये मजदूर बिहार, झारखंड, उत्तरप्रदेश, बंगाल जैसे राज्यों में अपने गांवों कस्बों में भी कोरोना संक्रमण लेकर पहुंच रहे हैं। इस संक्रमण को रोकने का सरकारी प्रयास ज्यादतर जगहों पर विफल है। भारत जैसे देश में करोड़ों लोगों की जांच और उन्हें क्वारेंटाइन करना उनका ईलाज करना असंभव है। इन सबके बावजूद अब कोरोना को लेकर कोई बेचैनी या भय नहीं है। आम भारतीय धीरे-धीरे ये स्वीकार कर रहा है कि कोरोना के साथ वह रह लेगा और अपने काम पर लौट जायेगा।आखिर ऐसा क्यों?

कोरोना से भय समाप्त होने का मूल कारण है भारत में संक्रमण की अपेक्षा इससे जान गंवाने वालों की संख्या का बहुत कम होना। याद किजिये महज आठ दस करोड़ की आबादी वाले इटली में बीस हजार से ज्यादा, स्पेन में तीस हजार, ब्रिटेन में40 हजार और अमेरिका में एक लाख से ज्यादा लोग कोरोना के कारण मौत के शिकार हुये हैं। चीन के बारे में तो वहीं की एक महिला ब्लॉगर ने लिखा है कि यहां कोरोना से आठ करोड़ लोग मरे हैं। चीन के बारे में ये सभी जानते हैं कि वह कभी सही आंकड़ा नहीं बतायेगा।

बहुत कम मौतों का क्या है कारण?

भारत में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, पर यहां लोग तेजी से ठिक होकर अपने घरों को लौट भी रहे हैं। अगर एक लाख चालीस हजार मरीज हैं तो उनमें एक्टिव मरीज सत्तर हजार ही हैं। अब तक देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या पांच हजार से भी कम है। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, स्पेन,जर्मनी,चीन,इरान सभी कोरोना से होने वाली बेतहाशा मौतों से हताश हैं।

आखिर क्या वजह रही कि भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या इतनी कम है? दरअसल इसके पीछे जो कारण हैं वह किसी दैवीय संयोग से कम नहीं हैं। अगर ये संयोग नहीं होता तो सरकारों की ये क्षमता नहीं थी कि वे इसे नियंत्रित कर पाते। भारतीयों में बचपन में लगे बीसीजी वगैरह के टीके, यहां का पारंपरिक भोजन, मसालों का उपयोग, मौसम और पहले से ही प्रदूषित वातावरण में रहने के कारण शरीर में पैदा हुई रोग प्रतिरोधकता ने भारतीयों को कोरोना से होने वाली मौतों से बचाये रखा है। ये फायदा सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप यानि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश सबों के साथ है।

भारत में संयोग से कोरोना संक्रमण तो बढा है, पर इतने बड़े देश में सवा अरब से ज्यादा की आबादी में अगर हम मौतों का आंकड़ा देखें तो यह एक राहत भरी तस्वीर पेश कर रहा है। सारे विश्व ने सबसे ज्यादा खतरा भारत को लेकर ही व्यक्त किया था। उनका मानना था कि एक बड़ा और अरबों की आबादी वाला भारत जहां बुनियादी स्वास्थ्य सुविधायें भी उपलब्ध नहीं वहां कोरोना घातक सिद्ध होगा और करोड़ो लोग मरेंगे। आज यहां लाखों संक्रमित हैं पर मरीज तेजी से ठिक भी हो रहे हैं यानि देश ने बड़ी संख्या में मौत की आशंकाओं को पूरी तरह से झूठला दिया है।

क्या खत्म होगा कोराना?

सब के मन में ये उम्मीद है कि कोरोना जिस तरह से आया उसी तरह से कुछ समय में बिल्कुल खत्म भी हो जायेगा और जिंदगी पहले की तरह ही आम हो जायेगी, पर चिकित्सकों से लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा सोंचना बेवकूफी है, कोरोना खत्म तो नहीं होगा, पर समय के साथ यह आम सर्दी खांसी का वायरस बन कर रह जायेगा, देश में यह मारक नहीं होगा? कुछ समय बाद इसकी दवा और वैक्सिन बन जायेंगे। फिलहाल देश में इसका भय अब खत्म हो रहा है और लोग यहां यूरोप अमेरिका की तरह इसके मारक न होने के कारण लापरवाह भी हो चले हैं।

अम्फान तूफान से बंगाल में खेती हरियाली की बर्बादी

20 मई को आए सुपर साइक्लोन अंफान ने न केवल पश्चिम बंगाल के उत्तर व दक्षिण 24 परगना तथा कोलकाता में जान-माल की क्षति पहुंचाई, बल्कि इससे माइक्रोक्लाइमेट और जैव विविधता को भी भारी नुकसान हुआ है। जादवपुर विश्वविद्यालय के स्कूल आफ ओसिनोग्राफिक स्टडीज के डायरेक्टर प्रो. तुहीन घोष ने कहा कि कम से तीन से पांच साल तक खेती-बाड़ी बुरी तरह प्रभावित होगी, क्योंकि नमकीन पानी का असर खत्म होने में वक्त लगेगा। इसके लिए मिट्टी की जांच कर जरूरत के मुताबिक मिट्टी में पोषक तत्त्व डालने होंगे। कोलकाता के आलावा सुंदरवन के सागरद्वीप, काकद्वीप, कुलतली, नामखाना, कैनिंग, हिंगलगंज वह अन्य जगहों पर भी पेड़ पौधों को भारी नुकसान पहुंचा है पर चक्रवात से नदी से किनारे लगे मैन्ग्रो को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पेड़ पौधों को जो नुकसान हुआ है, वो रिहाइशी क्षेत्रों में हुआ है। जो पेड़ पौधे बचे भी हैं, वे खारा पानी घुस जाने से झुलस गए हैं ।खारा पानी के रिहाइशी इलाके में प्रवेश कर जाने से खेती बारी बुरी तरह प्रभावित होगी।

सैकड़ों पेड़ यहां के लोगों के लिए जीविका का साधन थे। लोग लकड़ियों का इस्तेमाल खाना पकाने में करते थे और फर्नीचर बनाने के काम भी आता था। इसके आलावा पेड़ पौधे विभिन्न प्रकार की चिड़ियों, मधुमक्खियों वो सूक्ष्म जीवों का आवास थे। पेड़ों के गिर जाने इन्हें भी नुकसान होगा। सुंदरवन के वन्यजीवों को इससे कितना नुकसान हुआ है, इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी तक उन्हें किसी वन्यजीव का मृत शरीर नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि साइक्लोन सुंदरवन टाइगर रिजर्व के ऊपर से नहीं गुजरा है इसलिए वन्यजीवों को इससे नुकसान होने की संभावना कम है।

साइक्लोन के कारण केवल कोलकाता में 5500 पेड़ धराशाई हो गए हैं। बहुत से इलाकों से अब भी पेड़ों का हटाया जाना बाकी है। जानकारों का कहना है कि किसी भी इलाके में पेड़ पौधों की प्रचूरता उस खास इलाके के माइक्रोक्लाइमेट और जैवविविधता को प्रभावित करती है। ऐसे में 5500 पेड़ों का धराशाई हो जाने से कोलकाता पर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यहां जनसंख्या का घनत्व अधिक है।

पर्यावरणविद मोहित रे ने कहा, "कोलकाता के अलग-अलग हिस्सों में हम देखते हैं कि अलग तरह की जलवायु होती है। इसे माइक्रोक्लाइमेट कहा जाता है। मसलन जहां पेड़ ज्यादा होते हैं वहां का तापमान कम पेड़ वाले इलाके के मुकाबले कम होता है। पेड़ गिर जाने से उन इलाकों में तापमान बढ़ेगा। इसके आलावा जैवविविधता को भी नुकसान पहुंचेगा क्योंकि पेड़ पौधे केवल चिड़ियों का ठिकाना नहीं होते हैं। पेड़ों पर अति सूक्ष्म जीव भी होते हैं, जो जैवविविधता को बरकरार रखते हैं।

गौरतलब है कि कोलकाता में तापमान में तेजी से इजाफा हो रहा है। वैश्विक स्तर व अखिल भारतीय स्तर पर तापमान में सलाना जो इजाफा हो रहा है, कोलकाता में उससे 20 प्रतिशत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में कोलकाता में गर्मी बढ़ सकती है। मोहित ये ने कहा कि कोलकाता की जैवविविधता को पहले की स्थिति में आने में एक दशक लग सकता है और वह भी तब हो सकेगा, जब जहां भी पेड़ गिरे हैं, वहां जल्दी बढ़ने वाले पेड़ लगाए जाएंगे।

पौष्टिकता से भरपूर सुपर फ़ूड हैं मोटे अनाज

झारखण्ड में हैं इसकी बहुत संभावनायें

अजय कुमार

रांची : हाल में आयुष मंत्रालय के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में मोटे अनाज की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। पीएम मोदी बोले, 'आज हम देखते हैं कि जिस भोजन को हमने छोड़ दिया, उसे दुनिया ने अपनाना शुरू कर दिया है। जौ, ज्वार, रागी (मडुआ), कोदो, सामा, बाजरा, सांवा जैसे अनेक अनाज कभी हमारे खान-पान का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन ये अब हमारी थालियों से गायब हो गए है, जबकि अब पोषक से भरपूर इस आहार की पूरी दुनिया में भारी मांग है। भारत में हजारों वर्षों से मोटे अनाज का उत्पादन किया जाता रहा हैं। भारतीय हिंदू परंपरा के यजुर्वेद में मोटे अनाज का उल्लेख मिलता है। 50 वर्ष पहले तक मध्य और दक्षिण भारत के साथ पहाड़ी इलाकों में मोटे अनाज की खुब पैदावार होती थी।एक अनुमान के मुताबिक देश में कुल खाद्यान उत्पादन में मोटे अनाज की हिस्सेदारी करीब 40 फीसदी थी।

मोटे अनाजों में पोषक तत्वों की भरमार होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमें अपने भोजन में मोटे अनाज को शामिल करने और इसके खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। मोटे अनाज को पैदा

करने के लिए कम मेहनत और कम पानी की जरूरत होती है। मोटे अनाजों के गुणों के को देखकर केंद्र सरकार भी इन्हें बढ़ावा दे रही है। जिससे इन मोटे अनाजों के गुणों से समझा जा सकता है। मोटे अनाज में मक्का, रागी, ज्वार, बाजरा, जौ, कोदो आदि आते हैं।

झारखण्ड में मोटे आनाज की खेती की स्थिति

प्रदेश में कुछ वर्ष पूर्व तक खासकर गांवों में ग्रामीणों के बीच ज्वार, बाजरा और मडुआ की लिट्टी या रोटी प्रमुख खाद्य के रूप में प्रचलित थे। मोटे अनाज के रूप में इन खाद्य पदार्थों के सेवन से लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता था और धान या गेहूं पर निर्भरता भी कम रहती थी। किसान ज्वार, बाजरा और मडुआ की खेती भी उसी उत्साह से करते थे जैसे, धान या गेहूं के प्रति रहती है। लेकिन अब स्थितियां चुकी हैं। लोग अब मोटे अनाज की खेती से विमुख हो रहे हैं। यही कारण है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में ज्वार, बाजारा या मडुआ की खेती के आच्छादन में कमी हुई है। झारखण्ड के करीब 1 लाख 60 हजार एकड़ भूमि में रागी (मडुआ) की खेती होतो है। कमोबेश राज्य के सभी जिलों में इसकी खेती होती होती है , परन्तु इसके मुख्य उत्पादक जिले रांची, हजारीबाग एवं गिरिडीह है। प्रदेश के करीब 48 हजार 6 सौ एकड़ शुष्क भूमि में जौ की खेती की जाती है। बाजरा की खेती कम वर्षा वाले क्षेत्रों के करीब 22 एकड़ भूमि में की जाती है। प्रदेश में बाजरा उत्पादक मुख्य जिले हजारीबाग, रांची, सिंहभूम एवं संथाल परगना हैं। जबकि जौ के मामले में पलामु मुख्य उत्पादक जिला है। प्रदेश के करीब 5 हजार एकड़ शुष्क क्षेत्र एवं उच्च भूमि में ज्वार की खेती होती है। हजारीबाग, रांची, सिंहभूम एवं संथाल परगना ज्वार उत्पादक प्रमुख जिले है।इससे पता चलता है कि प्रदेश में मोटे आनाज के मामले में रागी (मडुआ) की सर्वाधिक खेती की जाती है। झारखण्ड राज्य में रागी (मडुआ) की खेती की संभावनाएँ प्रदेश में धान के बाद रागी (मडुआ) दूसरी प्रमुख खरीफ फसल है। परंपरागत खेती और स्थानीय किस्म के उपयोग कर कारण किसानों को 5-6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ही उपज मिल पाती है। जबकि उन्नत तकनीक एवं उन्नत किस्मों के प्रयोग से कम खर्च में 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची में आईसीएआर - अखिल भारतीय समन्वित स्माल मिलेट शोध परियोजना में अधिकतम ..... शेष पेज 4 पर

सीएमपीडीआई में आतंकवाद निरोध दिवस मनाया गया

रांची 21 मईः सीएमपीडीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एस0 सरन ने आतंकवाद निरोध दिवस के अवसर पर मुख्यालय एवं क्षेत्रीय संस्थान-3 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परम्परा में दृढ़ वि-श्वास रखते हुए सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करने तथा मानव जाति के सभी वर्गो के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की शपथ दिलायी।

इस मौके पर सीएमपीडीआई के निदेशक(तकनीकी/आरडीएंडटी)आर 0एन0 झा, निदेशक (तकनीकी/सीआरडी) श्री एस0के0 गोमास्ता, महाप्रबंधक एवं विभागाध्यक्षगण समेत अधिकारी एवं कर्मचारीगण एवं श्रमिक प्रतिनिधि उपस्थित थे।

जरूरतमंदों में वन विभाग और ग्रीन रिवोल्ट ने बांटा राशन

संवाददाता

रांची : डोरंडा स्थित वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के कैंपस में 23 मई को जरूरतमंदों के बीच वन विभाग एवं ग्रीन रिवोल्ट के सहयोग से राशन पैकेट का वितरण किया गया।

इस अवसर पर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पीआरओ तारकनाथ समेत दर्जनों कर्मी उपस्थित थे। इन सबों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये सभी जरूरतमंदों का हाथ सेनिटाइज करवाकर राशन पैकेट वितरण किया। जनसंपर्क अधिकारी तारकनाथ ने इस कार्य में सहयोग के लिये ग्रीन रिवोल्ट को धन्यवाद दिया और मदद की सराहना की। ग्रीन रिवोल्ट की ओर से राशन वितरण में मनोरंजन सिंह, मनोज शर्मा और विनोद कुमार ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया।

लॉकडाउन से कार्बन प्रदूषण 17प्रतिशत घटा

मुरलीधर

कोरोना महामारी के चरम के दौरान कई देशों ने लॉकडाउन लगाया था जिसका पर्यावरण पर सकारात्मक असर सभी ने देखा। एक शोध के मुताबिक कार्बन प्रदूषण महामारी के चरम पर 17 फीसदी कम हुआ है। इस कमी का कारण कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन को बताया जा रहा है। पिछले महीने कोरोना वायरस महामारी अपने चरम पर थी और उस दौरान देशों ने लॉकडाउन लागू किया हुआ था।

वैज्ञानिकों का कहना है कि जिंदगी सामान्य होने और गैस का स्तर बढ़ने से जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में प्रदूषण में थोड़े वक्त के लिए आई कमी "समुद्र में एक बूंद के समान" होगी। कार्बन डाइऑक्साइड पर अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया कि प्रदूषण का स्तर वापस लौटने लगा है, हालांकि 2019 के मुकाबले प्रदूषण का स्तर चार से सात फीसदी के बीच रहेगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह कार्बन उत्सर्जन में सबसे बड़ी वार्षिक गिरावट है। अगर लॉकडाउन के नियम पूरी दुनिया में साल भर सख्ती से लगाए गए तो यह सात फीसदी रहेगा और अगर पाबंदियां हटा ली गईं तो यह चार फीसदी रहेगा।

नेचर क्लाइमेट चेंज पत्रिका में छपे शोध के मुताबिक अप्रैल के एक हफ्ते में अमेरिका ने अपने कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में करीब एक तिहाई की कटौती की। दुनिया के सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देश चीन ने फरवरी में कार्बन डाइऑक्साइड में एक चौथाई की कटौती की। भारत ने जहां उत्सर्जन में 26 फीसदी की कटौती की तो वहीं यूरोप ने 27 फीसदी की कटौती की। सबसे बड़ी वैश्विक गिरावट 4 से लेकर 9 अप्रैल के बीच थी जब दुनिया रोजाना 17 मिलियन मेट्रिक टन कार्बन प्रदूषण पैदा कर रही थी। 2006 के बाद से इस तरह के वैश्विक उत्सर्जन के स्तर दर्ज नहीं किए गए हैं, लेकिन अगर दुनिया अगले साल धीरे-धीरे प्रदूषण के स्तर पर वापस लौटती है तो अस्थायी गिरावट समुद्र में एक बूंद के बराबर होगी।

यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया में जलवायु वैज्ञानिक और शोध की मुख्य लेखिका कोरिन्ने ले क्वेरे का कहना है कि अगर दुनिया अगले साल धीरे-धीरे बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर लौटती है, तो अस्थायी कमी में यह समुद्र की एक बूंद के बराबर होगी। ले क्वेरे कहती हैं, "यह वैसा ही जैसे आपके पास पानी से भरा बाथ टब है और आप 10 सेकंड के लिए नल बंद कर दे रहे हैं " 30 अप्रैल तक विश्व कार्बन प्रदूषण का स्तर महीने के शुरुआती बिंदु से बढ़कर प्रतिदिन 30 मेट्रिक टन हो गया था।

बाहरी विशेषज्ञों ने अध्ययन को सबसे व्यापक बताया है और कहा है कि इससे पता चलता है कि कार्बन उत्सर्जन को खतरनाक स्तर तक जाने से रोकने के लिए कितनी कोशिशों की जरूरत है। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में जलवायु वैज्ञानिक माइकल मान के मुताबिक, "यह एक सरल सत्य को रेखांकित करता है।।अकेले व्यक्तिगत व्यवहार से हम यहां नहीं पहुंच सकते हैं। हमें मूलभूत रचना संबंधी परिवर्तन की जरूरत है।शोध के लेखकों का मानना है कि बिना किसी महामारी के ही दुनिया कार्बन उत्सर्जन में कुछ दशकों के लिए कटौती कर लेती है तो ऐसा मुमकिन है कि धरती को एक डिग्री गर्म होने से बचाया जा सकता है। शोध के लेखकों का कहना है कि उत्सर्जन में आधी कटौती कम परिवहन की वजह से हुई है, जिसमें ज्यादातर कार और ट्रक शामिल हैं। ●

इस अव्यवस्था से बचा जा सकता था

जब से ट्रेन और बसों से मजदूरों को उनके गांव भेजने का काम शुरू हुआ है तब से उन राज्यों में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या एकाएक बढने लगी है जहां अब तक कोरोना मरीज बहुत कम थे। झारखंड बिहार जैसे राज्यों में हाल में एकाएक मरीजों की संख्या अपने घर आ रहे मजदूरों के कारण बढ़ गयी है। इसके अलावा एक और परेशनी भी हो रही है कि अब जब ये मजदूर अपने गांव पहुंच रहे हैं तो हजारो किमी की दूरी जैसे तैसे पूरी कर अपने घर पहुंचने के बाद गांव के बाहर क्वारेंटीन होकर रह रहे हैं, ये अगर स्वस्थ भी हैं तो इनका अपना परिवार शंका की नजर से ही देख रहा है और इन्हें अपनों से दूर रहना पड़ रहा है। इनमें से कुछ क्वारेंटीन सेंटरों से ये भाग रहे हैं पुलिस को इन्हें पकड़ने की मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं क्वारेंटीन सेंटरों में ये घटिया भोजन और अव्यवस्था की शिकायत कर रहे हैं।

केंद्र सरकार भले ये कह कर अपनी पीठ थपथपा ले कि समय पर लॉकडाउन करके हमने बड़े नुकसान से लोगों को बचा लिया, पर ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि लॉकडाउन के निर्णय में एक बड़ी चूक हुई कि करोड़ो दिहाड़ी मजदूरों को वो जहां थे वहीं सख्ती से रोक दिया गया जिससे उनके खाने के लाले पड़ गये। वहां की राज्य सरकारें इनका पूरा ख्याल रखने में विफल रहीं, राजनीति करने लगीं और जब इन मजदूरों में संक्रमण फैल गया तो ये कोरोना ढोकर अपने गांव ले जा रहे हैं।

केंद्र ने शुरुआत में ही एक बड़ी गलती कर दी कि जब संक्रमितों की संख्या सौ दो सौ थी उस वक्त रोज कमाने खाने वाले मजदूरों को कैद कर दिया और जब संक्रमण बढ़ गया तो उन्हें उनके राज्यों में भेजा जा रहा है। इससे बेहतर था कि प्रारंभ में ही इन्हें इनके गांव भेज दिया जाता।

जब स्थिति खराब हो गयी है तो मजदूर सड़कों पर जैसे तैसे पैदल, साइकिल से ही अपने घर को निकल पड़े। दुर्घटनाओं में इनकी जान जा रही है, रास्ते में बीमार पड़ रहे हैं कई जगहों पर तो इनके साथ लूट पाट होने की भी खबर है। लॉकडाउन का निर्णय बिल्कुल सही और समय पर लिया गया था, पर करोड़ो मजदूरों को जहां तहां जबरन रोकना कहीं से भी उचित नहीं था। क्योंकि भारत जैसे भ्रष्ट देश में ये संभव नहीं कि मजदूरों को खिलाने के लिये मिले राशि और राशन को ईमानदारी से खर्च किया जा सके।

झांसी पहुंचा पाकिस्तान का टिड्डी दल

पाकिस्तान की धरतीं से चला करोड़ों टिड्डियों का दल राजस्थान व हरियाणा में खेतों में तबाही मचाता हुआ शुक्रवार को झांसी पहुंच गया। अचानक आसमान में करोड़ों की तादाद में कीट मंडराने लगे। अनहोनी की आशंका के चलते लोग खिड़की - दरवाजे बंद कर घरों में कैद हो गए। टिड्डियों को भगाने के लिए कहीं थाली बजाई गईं तो कहीं धुआं भी किया गया।

शुक्रवार की शाम तकरीबन पांच बजे अचानक महानगर में आसमान में करोड़ों की संख्या में कीट मंडराने लगे। सबसे पहले इन्हें ग्वालियर रोड के इर्दगिर्द के इलाकों में देखा गया। यहां से आगे बढ़ता हुआ टिड्डियों का दल महानगर में प्रवेश कर गया। गनीमत ये रही कि ये कीट आसमान में उड़ते हुए आगे बढ़ते गए। बावजूद, एक साथ इतनी भारी तादाद में कीट नजर आने पर लोग अनहोनी की आशंका करने लगे। कीट घरों में प्रवेश न कर जाएं, इसके लिए एहतियातन लोगों ने खिड़की - दरवाजे बंद कर लिए। नारायण बाग के इर्दगिर्द के इलाके में हरियाली नजर आने पर टिड्डियों का दल काफी देर तक मंडराता रहा।ग्रामीण क्षेत्रों में भी यही स्थिति बनी रही। सब्जियों की खेती करने वाले किसानों ने पौधों पर बैठे कीटों को खेतों में थाली बजाकर व अन्य प्रकार से तेज आवाज कर तथा धुआं कर भगाया। टिड्डियों का दल आसमान में उड़ता हुआ ललितपुर की ओर आगे बढ़ता देखा गया।

आर्थिक स्वायत्तता से सुधरेगा कृषि क्षेत्र

अजय शाह

देश का खाद्य बाजार कठिनाइयों से भरा हुआ है। हालांकि हाल में जो घोषणाएं की गई हैं वे इन समस्याओं को दूर करने की दिशा में अहम हैं। निजी व्यक्तियों के लिए तीन अहम निर्णयों पर ध्यान केंद्रित करना महत्त्वपूर्ण है: बीज रोपण कैसे हो, कितना निवेश किया जाए और क्या भंडारित किया जाए। इसके अलावा बेहतर निर्णय के लिए प्रोत्साहन भरे माहौल पर विचार करना भी इसका हिस्सा है। इससे आगे की राह में कम से कम सरकारी हस्तक्षेप, भंडारण, वायदा बाजार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार आदि शामिल हैं।

पॉल सैम्यूलसन कृषि को लेकर एक दंतकथा कहते थे जिसका नाम था कॉबवेब मॉडल। अच्छी फसल के बाद कीमतों में गिरावट आती है और फिर बुआई का रकबा कम होता है, इससे कीमतों में उछाल आती है और पुनः बुआई बढ़ती है। यह कष्टकारी चक्र चलता रहता है। हम बार-बार तेजी और गिरावट के इस दुष्चक्र के साक्षी बनते रहे हैं। बाजार अर्थव्यवस्था इन समस्याओं को कैसे हल करती है? यहां निजी व्यक्तियों के तीन बड़े निर्णयों पर ध्यान केंद्रित करना महत्त्वपूर्ण है: कौन सी फसल की बुआई की जाए, कच्चे माल में कितना निवेश किया जाए और क्या भंडारण किया जाए? जब ये निर्णय सही ढंग से लिए जाते हैं तो खाद्य बाजार बेहतर काम करता है। सवाल यह है कि वह कौन सा माहौल है जिसके तहत निजी व्यक्ति ऐसे निर्णय आसानी से ले सकें? इसके लिए चार तत्त्वों की आवश्यकता है।

इसके लिए बाजार आधारित भंडारण तंत्र की आवश्यकता है ताकि मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली और केंद्रीय भंडारण से निजात पाई जा सके। निजी स्तर पर लोग भविष्य पर नजर रखेंगे, भविष्य की कमियों का अनुमान लगाएंगे और प्रतिक्रिया स्वरूप भंडारण करेंगे। निजी स्तर पर लोग भविष्य में होने वाली कमी का अनुमान कैसे लगाएंगे? किसान आखिर कैसे तय करेगा कि कितनी जमीन में बुआई की जाए और कौन सी फसल लगाई जाए? इस मामले में सबसे महत्त्वपूर्ण है वायदा बाजार। वायदा बाजार निजी व्यक्तियों को खाद्य अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करता है और भविष्य की कीमतों का पूर्वानुमान लगाता है। एक व्यवस्थित वायदा बाजार के साथ निजी व्यक्ति भविष्य की कीमतों के बारे में अनुमान से लाभान्वित हो सकता है। वह अपनी बुआई और भंडारण को लेकर भी इसी आधार पर निर्णय ले सकता है। यह ऐसा क्षेत्र है जहां वायदा कारोबार पर भारी प्रतिबंध हटाने की आवश्यकता है। भारतीय बाजार को वैश्विक वायदा बाजार से जोडने की जरूरत है और भारत को व्यवस्थित वित्तीय बाजारों से जोडने की भी।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्थिरता का अच्छा माध्यम है। जब देश में किसी तरह का गतिरोध उत्पन्न होता है और कीमतों में गिरावट आती है निर्यात करना देश के हित में होता है। जब देश में कमी होती है और कीमत में उछाल आती है तो आयात करना देश के हित में होता है। यहां भी निजी स्तर पर लोगों के कदम यह निर्धारित करने का काम करते हैं कि आयात करना है या निर्यात। ऐसे में यह अहम है कि वैश्विक बाजार के साथ एकीकरण के क्रम में निजी फर्म की संगठनात्मक क्षमता में भी इजाफा हो। जब एक सरकार लोगों को प्रतिबंध लगाने या हटाने जैसे कदमों में उलझाती है तो संगठनात्मक क्षमता का विकास नहीं होता है।

चौथा घटक है देश के भीतर व्यापार यानी आंतरिक व्यापार का। भारत एक बड़ा और विविधतापूर्ण देश है। काफी हद तक यह यूरोपीय संघ जैसा है। देश के भीतर व्यापार भी स्थिरता का एक बड़ा जरिया है। इसके लिए तमाम तरह के सरकारी हस्तक्षेप समाप्त करने की आवश्यकता है। खरीदारों और विक्रेताओं को कहीं भी सफर करने और व्यापार करने की पूरी छूट होनी चाहिए। भारत को श्रम आधारित और उच्च मूल्य वाले कृषि निर्यात में शामिल होने की पर्याप्त वजह मौजूद है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि गेहूं और चावल जैसी पूंजी आधारित खेती कम की जाए। अगर ये चारों तत्त्व व्यवस्थित हों यानी भंडारण, वायदा कारोबार, घरेलू व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुचारु हों तो निजी क्षेत्र के लिए निर्णय लेने को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इससे भारतीय कृषि में तेजी और गिरावट की निरंतरता का दुष्चक्र और निरंतर कम आय का संकट दूर करने में भी मदद मिलेगी।

हाल में की गई घोषणाएं भंडारण और राष्ट्रीय बाजार से संबंधित हैं। ये बिल्कुल सही दिशा में की गई हैं। तेज और तकनीकी रूप से मजबूत क्रियान्वयन समय की मांग है। मौजूदा हस्तक्षेप की बात की जाए तो यह काफी जटिल है। इसमें संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य सरकारों के कानूनों की बदौलत स्वायत्तता को कई तरह से सीमित किया गया है। इनका सावधानीपूर्वक वैधानिक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। इसके आधार पर ही एक नया कानून तैयार करने की वैधानिक नीति तैयार की जा सकेगी। एक ऐसा कानून जो भंडारण और राष्ट्रीय बाजार में स्वायत्तता प्रदान करे। एक अहम विचार यह भी है कि संविधान के अनुच्छेद 301 का समुचित इस्तेमाल किया जाएग। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि देश भर में व्यापार और वाणिज्य निःशुल्क होना चाहिए। इससे केंद्र सरकार के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार तैयार करने की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा संस्थागत व्यवस्था तैयार करके प्रशासनिक बाधाओं को समय-समय पर न केवल चिह्नित किया जा सकता है बल्कि खाद्य बाजार के व्यापार में आने वाली ऐसी बाधाओं की समीक्षा भी की जा सकती है। अनिरुद्ध बर्मन, इला पटनायक, शुभ रॉय और मैंने जो एक पर्चा लिखकर यह वैधानिक विश्लेषण किया है।

खाद्य बाजार में ऐसे तमाम प्रतिबंध हैं जो निजी स्तर पर लोगों के तीन बड़े निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अल्पावधि में न केवल पूरी तरह बाजार आधारित व्यवस्था लागू हो जाएगी बल्कि कई तरह के सुधारात्मक कदमों की भी आवश्यकता होगी। अल्पावधि में कई नीतिगत पहल ऐसी होंगी जो आंशिक तौर पर ऐसे प्रभाव उत्पन्न करें जो शायद सुखद न हों। इसके अलावा बाजार आधारित खाद्य व्यवस्था में पूरी तरह शामिल होने और पूर्ण लाभ हासिल करने के लिए भी काफी काम करने होंगे।

खाद्य बाजार इस बात का परिचायक है कि कैसे भारत की पारंपरिक विकास संबंधी सोच नाकाम रही। नीतिगत विफलता की बात करें तो विकास आधारित राज्य, केंद्रीय नियोजन, मानव स्वतंत्रता का दमन आदि ने मिलकर खराब नतीजे ही दिए। हर कदम पर हमारे गड़बड़ बौद्धिक ढांचे ने ऐसे नीतिगत कदमों की जगह बनाई जिनके अनचाहे परिणाम सामने आए। देश में व्यापक गरीबी समाप्त करने की राह खाद्य एवं अन्य क्षेत्रों की इन्हीं बुनियादों पर सवाल उठाने से जुड़ी है।

(लेखक नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनैंस ऐंड पॉलिसी, नई दिल्ली में प्रोफेसर हैं।)

प्लाज्मा जेट इंजन से क्या उत्सर्जन हो जाएगा शून्य?

देवांशु दत्ता

कोविड महामारी की वजह से वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन में भारी कमी आई है। इसके अलावा भी पर्यावरण पर कई अन्य सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। अगर उत्सर्जन में कटौती अधिक टिकाऊ हो जाती है तो यह एक अच्छा नतीजा होगा।

लॉकडाउन के दौरान यात्राओं पर पाबंदी लगी होने से परिवहन-संबंधी उत्सर्जन काफी नीचे आ गया है। इसकी वजह यह है कि विमानों, ट्रेनों एवं सार्वजनिक परिवहन के सारे साधन बंद पड़े हुए हैं। कामकाजी दफ्तरों और शिक्षण संस्थानों ने वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की है। ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन और वेबिनार आज के दौर का नया चलन हैं। इसके अलावा तमाम उद्योग बंद होने से बिजली की मांग भी कम हुई है। यात्रा, व्यापार एवं उद्योग में समय बीतने के साथ रौनक लौट आएगी। लेकिन वेबिनार और घर से काम करने की नई प्रवृत्ति शायद स्थायी बदलाव हो सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संवाददाता सम्मेलन करना कंपनियों के लिए एक बड़ी बचत का सबब बन सकता है और तकनीक ने इस बात को साबित भी किया है।

नागरिक उड़ानों का एक सामान्य वर्ष में होने वाले वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में करीब 2.5 फीसदी अंशदान होता है। अगर वाणिज्यिक उड़ानों की संख्या में कमी आती है तो फिर इस उत्सर्जन में भी गिरावट आएगी। जहाजों के परिचालन में नई स्वच्छ ईंधन तकनीक को अभी जनवरी 2020 में ही अपनाया गया है जिससे उत्सर्जन में कुछ कमी आएगी।

लंबे समय में विमानन संबंधी कार्बन उत्सर्जन को कम करने में एक और तकनीक काफी कारगर हो सकती है। केरोसिन या विमान ईंधन पर चलने वाले जेट इंजन। एक ऐसे जेट इंजन की कल्पना करें जो स्वच्छ स्रोत से पैदा हुई बिजली का इस्तेमाल करता है और उसे किसी भी तरह के जीवाश्म ईंधन की जरूरत नहीं है।

प्लाज्मा जेट इंजन की अवधारणा को लेकर काफी शोध कार्य हो रहे हैं और इस दिशा में कुछ उल्लेखनीय कामयाबी भी मिली है। एक परंपरागत जेट इंजन ईंधन जलाता है और बेहद प्रदूषित गर्म हवा पैदा करता है। यह गर्म हवा उच्च दबाव पर एक ट्यूब से होकर गुजरती है और टर्बाइन से जाकर टकराती है। फिर टर्बाइन के पंखे तेजी से घूमने से ऊर्जा पैदा होती है और हवा विमान के पिछले हिस्से से बाहर निकल जाती है। न्यूटन के तीसरे सिद्धांत के मुताबिक हरेक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, लिहाजा पीछे की तरफ हवा का प्रवाह होने से विमान आगे की तरफ बढने लगता है। अब जरा यह कल्पना करें कि हवा को गर्म करने के लिए ईंधन जलाने के बजाय सूक्ष्म तरंगें ही हवा में बिजली चार्ज के लिए निर्देशित करें। यह ऑयनीकरण की स्थिति पैदा करता है। गैसों से उनके इलेक्ट्रॉन छीन लिए जाते हैं और एक सकारात्मक चार्ज के साथ वह प्लाज्मा में बदल जाता है। एक विद्युत-चुंबकीय क्षेत्र होने से प्लाज्मा तेजी से धक्का देता है और विमान को आगे बढने की ताकत मिलती है।

प्लाज्मा प्रक्षेपकों का इस्तेमाल अंतरिक्षयानों में हो चुका है। शुरुआती प्लाज्मा प्रक्षेपकों का इस्तेमाल 1960 के दशक में ही हुआ था। लेकिन ये प्रक्षेपक काफी कमजोर हैं और वायुमंडल में काम करने के लिए सक्षम नहीं हैं और उन्हें जेनॉन गैस के तौर पर अपना खुद का ईंधन लेकर जाना होगा। वर्ष 2018 में एमआईटी की एक शोध टीम ने प्लाज्मा ऊर्जा से लैस मा-इक्रोलाइट ग्लाइडर का प्रदर्शन कर यह दिखाया कि सापेक्षिक रूप से कमजोर धक्का होते हुए भी यह वायुमंडल में काम कर सकता है।

हाल ही में वुहान यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल साइंसेज द्वारा प्रकाशित एक शोध-पत्र में दावा किया गया है कि इंजीनियरों के एक दल ने इस धक्के को परंपरागत जेट इंजन के बराबर पाया है। शोध दल ने 2.45 गीगाहट्र्ज ऑयनीकरण चैंबर में पैदा उच्च तापमान एवं उच्च दबाव वाले प्लाज्मा पर अत्यधिक दबाव के साथ हवा फेंकी। शोध-पत्र के मुताबिक, इस तरीके से वाणिज्यिक जेट विमानों के समान विमान को आगे की ओर धक्का देने वाली प्रणोदन शक्ति और जेट दबाव हासिल की जा सकती है। इस प्रायोगिक परीक्षण में ट्यूब के ऊपर स्टील की एक खोखली गेंद भी लगाई गई थी। उच्च दबाव वाले प्लाज्मा को इस ट्यूब में प्रवाहित किया गया और उसमें आग लगा दी गई। इससे गेंद पर जबरदस्त धक्का लगा और वह चारों तरफ घूमने लगी। प्लाज्मा का प्रवाह टिकाऊ बनाए रखने के लिए ट्यूब के भीतर सामान्य हवा को भी प्रवाहित किया गया था। इस स्टील गेंद में नियंत्रित तरीके से द्रव्यमान भी डाला गया क्योंकि विद्युत क्षेत्र की ताकत अलग-अलग दर्ज की गई। इस दौरान गेंद की आवाजाही को मापा गया और गैर-प्लाज्मा वायु प्रवाह के लिए भी गुंजाइश छोड़ी गई। शोधपत्र कहता है कि 310 किलोवॉट समकक्ष ऊर्जा वाली एक मानक टेस्ला बैटरी का इस्तेमाल करें तो परीक्षण के दौरान करीब 8500 न्यूटन की ताकत पैदा हो सकती है। एक न्यूटन का आशय उस शक्ति से है जो एक किलोग्राम वजन को एक मीटर प्रति सेकंड की गति से हटाने के लिए चाहिए होता है। इस तरह प्रायोगिक परीक्षण के दौरान प्लाज्मा तकनीक से पैदा हुई ऊर्जा परंपरागत जेट इंजन के बराबर ही होनी चाहिए।

ऐसी स्थिति में शोधपत्र इस संभावना को स्वीकार करता है कि आगे चलकर एक ऐसा सूक्ष्म-तरंग वाला प्लाज्मा जेट प्रक्षेपक बनाया जा सकता है जिससे कार्बन उत्सर्जन एवं वैश्विक तापमान से बचने में मदद मिलेगी। हालांकि इस संकल्पना को कार्यरूप में ढालने की राह में अभी कई चुनौतियों से पार पाना होगा। सच है कि इस परीक्षण के दौरान काफी अधिक गर्मी पैदा हुई। ऐसे में इतने ऊंचे तापमान का उपकरण पर असर एवं धक्के को संभालने जैसे मामलों से निपटना भी खासा मुश्किल होगा। अगर एक कार्यशील प्लाज्मा जेट इंजन बन जाता है तो विमानन क्षेत्र में उत्सर्जन का स्तर लगभग शून्य हो जाएगा।

पीपीई किट में काम करना डॉक्टरों को बना रहा है बीमार

कोरोना संकट के कारण दुनिया भर में डॉक्टर काम के बोझ तले दबे हैं। कोरोना के ईलाज में लगे डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को बचाव के लिए जरूरी पीपीई किट हमेशा पहने रहना पड़ता है। उन्हें इस गर्मी में लगातार 6 से 10 घंटे इसे पहने रहने से मुश्किल होती है। वह कहते हैं, "किट पहनने के बाद कुछ खाना-पीना तो दूर, टॉयलेट तक नहीं जा सकते। शुरू शुरू में तकलीफ अधिक होती थी लेकिन अब आदत में शुमार हो गया है। इसके बावजूद ज्यादतर डॉक्टर थकान, बेचैनी और तनाव के शिकार हो रहे हैं। कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर रही सीनियर न्यूरोलोजिस्ट डॉ अर्चना वर्मा का कहना है, "नींद नहीं आती, आंखों के सामने अस्पताल और मरीजों का चेहरा घूमता रहता है।" पीपीई किट में 10 घंटे काम करना बेहद थका देने वाला होता है। डॉ अर्चना बताती हैं, ऐसी स्थिति में काम पर फोकस बनाए रखना आसान नहीं होता,खुद को लगातार रीचार्ज करते रहना पड़ता है।

लंबे समय तक पीपीई पहनने से हाइपोक्सिया जैसे लक्षण आ रहे हैं।

लंबे समय तक पीपीई पहनने से हाइपोक्सिया जैसे लक्षण आ रहे हैं। मानसिक और शारीरिक थकान तो इससे हो ही रहा है। इसके अलावा क्लॉस्ट्रोफोबिया, घुटन, उलझन और डिहाइड्रेशन की समस्या भी सामने आ रही है। डॉ राजेन्द्र उइके कहते हैं कि शुरू में उन्हें शरीर में जलन और धुंधला दिखने की समस्या तक आई थी।

विश्व का इकलौता घड़ियाल अभयारण्य

घड़ियाल पूरे विश्व में केवल गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, सिन्ध तथा चम्बल में ही पाए जाते थे। वर्ष 1974 में सिन्ध नदी में लगभग 70 घडियाल थे किन्तु अस्सी के दशक में सिन्ध नदी में एक भी घड़ियाल शेष नहीं रहा। वैज्ञानिकों ने बताया कि इन जलचरों की प्रजातियों के समाप्त होते जाने का प्रमुख कारण उनके नैसर्गिक निवास स्थलों का नष्ट होना, चमड़े के लिए शिकार किया जाना तथा मछली पकड़ने के जालों में फंस जाने के कारण डूबने से मर जाना बताया। अतः भारत सरकार ने घड़ियाल के पुनर्वास की व्यापक योजना बनाई जिसके तहत घडियालों एवं मगरमच्छों के अण्डों से बच्चे तैयार कर उन्हें फिर से नदियों में छोड़ा जाना सम्मिलित था। चम्बल नदी घडियालों के लिए बेहतर प्राकृतिक आवास है। घड़ियालों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा रास्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी।

प्रकृति के साथ अनुचित संवाद और अर्थव्यवस्था पर समीक्षा हो

एजेंसियां

वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद आर्थिक सिद्धांतों और नीतियों के कई पहलुओं की नए सिरे से समीक्षा करनी पड़ी थी। खासतौर पर उनकी जिनका संबंध वित्तीय नवाचार और नियमन से था। ऐसा होना भी चाहिए। कोई भी अनुशासन चाहे वह अवधारणा के स्तर पर हो या व्यवहार के, ऐसे बड़े झटके के आलोक में उसकी समीक्षा होनी ही चाहिए। कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण उत्पन्न मौजूदा आर्थिक और जन स्वास्थ्य संकट के दौरान भी ऐसी समीक्षा आवश्यक है। रुख में बदलाव के संकेत नजर भी आने लगे हैं। उदाहरण के लिए यह एकदम स्पष्ट है कि आर्थिक गतिविधियों के पर्यावरण प्रभाव की अब तक खास चिंता नहीं की गई पर अब इन्हें केंद्र में लाना होगा। जन स्वास्थ्य संकट के कुछ पहलू ऐसे हैं जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के पहलुओं को लेकर चूकों को उजागर करते हैं। कोरोनावायरस महामारी के दौरान शुरुआती कदम आवश्यक था, भले ही उसकी कीमत ज्यादा चुकानी होती। ऐसा करने से बाद में और अधिक कीमत चुकाने से बचा जा सकता था। जलवायु परिवर्तन को लेकर भी हमें ऐसा ही रुख अपनाने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भविष्य में हमें जो कीमत चुकानी पड़ सकती है वह अर्थव्यवस्था पर वैसे ही असर डालेगी जैसा कि कोरोनावायरस को नकारने ने डाला।

प्रकृति के साथ अनुचित संवाद को भी आर्थिक विचार प्रक्रिया में शामिल करने की आवश्यकता है। काफी संभावना है कि कई अन्य वायरस की तरह कोरोनावायरस भी वुहान में उभरा। ऐसा जानवरों और मनुष्यों के आपसी संपर्क के कारण हुआ। कोरोनावायरस के मामले में शायद वुहान के पशु-पक्षी बाजार ने वायरस के केंद्र के रूप में काम किया। औद्योगिक कृषि में भी ऐसे मामले सामने आते हैं, भले ही वे कम खतरनाक हों। मांस, डेरी और मुर्गीपालन उद्योग ने अतीत में मैड काऊ जैसी बीमारी को जन्म दिया है। इस बहस में पशु अधिकार से जुड़े सवाल भी आते हैं लेकिन अर्थशास्त्री उन पर विचार नहीं करते। खेती के भविष्य पर भी सावधानीपूर्वक विचार करना होगा और इसकी लागत को लेकर अधिक एकीकृत तरीका अपनाना होगा। क्या जैविक या हाइड्रोपोनिक (बिना मिट्टी के) खेती से होने वाली उपज कभी उर्वरक आधारित खेती जैसी उपज दे पाएगी।आखिर में वैश्विक व्यापार की प्रकृति की बात करें तो वह सर्वाधिक किफायती नेटवर्क्स के इर्दगिर्द तैयार की गई है। इस बारे में भी नए सिरे से विचार करना होगा। वित्तीय संकट ने वित्त जगत को मजबूर किया कि वह इस बात की समीक्षा करे कि उसके रिटर्न और संकट को लेकर उसके जोखिम के बीच सही संतुलन है या नहीं। पूंजी पर्याप्तता की आवश्यकता में इजाफा किया गया, पूंजी की किफायत कम की गई और इसके साथ ही एक और संकट की संभावना भी कम की गई। इसी प्रकार मौजूदा वैश्विक आपूर्ति शृंखला शायद कुछ खास भौगोलिक क्षेत्रों पर अत्यधिक निर्भरता की शिकार हों। या फिर कम से कम वे इतनी मजबूत तो नहीं हैं कि वे शृंखला में कुछ कडियों की नाकामी का बोझ वहन कर सकें।ये ऐसे सवाल हैं जो हमेशा से आर्थिक विश्लेषण का हिस्सा रहे हैं लेकिन उन्हें अब तक पार्श्व में रखा गया।

इस अप्रत्याशित संकट के आकार और इसकी व्यापकता को देखते हुए यह मुद्दा तथा ऐसे अन्य मुद्दों की और अनदेखी नहीं की जा सकती है। नीति निर्माताओं और अकादमिक अर्थशास्त्रियों दोनों को इस बात का पुनरीक्षण करना होगा कि वे पर्यावरण संबंधी अनुमानों, प्राकृतिक दुनिया के साथ संपर्क और उच्च किफायत वाली आपूर्ति शृंखला आदि को लेकर किस प्रकार विचार करते हैं। शायद यह सही वक्त है कि हम उन संभावित जोखिमों का आकलन करेंगे जो वित्तीय तंत्र में उत्पन्न जोखिमों की तुलना में कहीं अधिक बड़े हो सकते हैं।

प्रवासी मजदूरों की वजह से बढ़ रही है यूपी में संक्रमण की रफ्तार

उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों की वापसी की बढ़ती दर के साथ अब शहरों के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी कोविड संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ने लगी है। कई जिले जहां अब तक कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या इकाई में थी, वहां अब एक दिन में ही दर्जनों लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। वहीं बिहार में संक्रमित लोगों में करीब 46 फीसद लोग प्रवासी बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या छह हजार के करीब है। राज्य सरकार के मुताबिक, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों और बसों से अब तक बीस लाख लोग अपने घरों को वापस लाए जा चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दूसरे राज्यों से आए अब तक 1041 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जो कि राज्य में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों का करीब एक चौथाई है। यह स्थिति तब है जबकि बड़ी संख्या में अभी लोग लौट रहे हैं और जो लौटे भी हैं उनमें से ज्यादातर अभी क्वारंटीन में हैं ।

स्पेशल ट्रेन से आए यात्रियों में खाद्य पदार्थ और वस्तुओं का वितरण

रांची :दक्षिण पूर्व रेलवे सर्वो की अध्यक्षा रीता महांति के मार्गदर्शन में 22मई को ट्रेन संख्या 01642 उडीपी (कर्नाटक) से हटिया आने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आने वाले सभी श्रमिक यात्रियों को सर्वो द्वारा खाद्य पदार्थ एवं दैनंदिन उपयोग में आने वाली वस्तुओं का वितरण किया गया। दक्षिण पूर्व रेलवे सर्वो समिति सदैव सामाजिक कार्य में अग्रणी रहती है इसी कड़ी मे जो श्रमिक उडीपी से हटिया आए उन्हे सहायता प्रदान की गयी इस कार्य को सफल बनाने में रांची रेल मंडल, सर्वो की अध्यक्षा श्रीमती रूबी अम्बष्ठ, सर्वो की अन्य पदाधिकारी एवं सदस्याओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

लॉकडाउन के कारण बढ़ गया टिड्डियों का हमला

खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) का मानना है कि लॉकडाउन ने टिड्डी दल को फैलने में बड़ी मदद की है। अप्रैल के मध्य में भारत, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में एफएओ के अधिकारियों ने कोरोनावायरस के कारण हुए लॉकडाउन के असर पर चर्चा की थी। बैठक में एक चिंताजनक तथ्य यह पता चला था कि लॉकडाउन के कारण ईरान ने टिड्डी दलों को मारने के लिए केमिकल का छिड़काव रोक दिया है। इस बैठक में एफएओ के अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि टिड्डी दलों के रोकथाम के अभाव में इनका लगातार प्रजनन होगा और हालात बेकाबू हो जाएंगे। उन्होंने चेताया था कि ये टिड्डी दल भारत के नए भौगौलिक क्षेत्रों और पड़ोसी देशों का रुख करेंगे।

ईरान ने मार्च और अप्रैल में लॉकडाउन का हवाला देकर टिड्डी दलों को नियंत्रित करने के तमाम उपायों को रोक दिया। ईरान की पूरी सरकारी मशीनरी कोरोनावायरस से लड़ाई में जुट गई और टिड्डी दलों पर ध्यान नहीं दिया गया।

देश और मजबूत होगा: इंद्रेश कुमार जी

राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में इंद्रेश कुमार जी ने कहा कि कोविड 19 के पश्चात भारत के मजबूती की ओर निखरने के संकेत

संवाददाता

राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच(फैंस) झारखण्ड इकाई द्वारा राष्ट्रीय वेबिनार विषयक कोविड 19 में निखरा मज़बूत भारत सिस्को वेबेक्स मीटिंग ऐप्प पर आयोजित किया गया ' इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता इंद्रेश कुमार जी, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के मार्गदर्शक सह संरक्षक,राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकरिणी सदस्य ने कहा कि कोविड 19 वैश्विक महामारी से भारत सहित दुनिया के कई देश दुष्प्रभावित होने के वावजूद भारत के एक मज़बूत स्तंभ के रूप में उभरने के संकेत हैं।

अध्यक्ष पवन बजाज ने सत्र में स्वागत भाषण देने के साथ वर्तमान स्थिति से निपटने में समाज एवं समुदाय डॉक्टरों की दी जाने वाली आपातकालीन सेवाओं की भूमिका और इस 'जंग' से बहादुरी के साथ लड़ने मे मदद किये जाने पर विचार ब्यक्त किया फैंस के उपाध्यक्ष डॉ संदीप कुमार ने राष्ट्रीय वेबिनार के मुख्य व्यक्ता माननीय इंद्रेश कुमार जी का परिचय कराया ।

इंद्रेश कुमार जी ने अपने संबोधन में कहा कि मोदी जी द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज से कुटीर उद्योग, लघु-मंझोले उद्योग, श्रमिक, किसान और मध्यम वर्ग को फायदा मिलेगा. साथ ही आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत को भी नई ताकत देगा। उन्होंने कहा कि यह वैश्वीकरण एवं उदारीकरण खासकर विकास के विदेशी पूंजी आधारित मॉडल पर आधारित वर्तमान नीति से सुखद विदाई है 'स्वदेशी स्वालंबन अभियान' से मंच देश में'स्वेदेशी' एवं आत्मनिर्भरता के महत्व पर जागरूकता पैदा करेगा, आत्मनिर्भरता छोटे उद्योगों, छोटे व्यापारियों, शिल्पियों और ग्रामीण उद्योगों समेत स्वदेशी उद्योग में जान फूंककर हासिल किया जा सकता है और उसका लक्ष्य रोजगार सृजन में रफ्तार के साथ ही समावेशी वृद्धि हो। देश में आयातित उत्पादों पर निर्भरता के लिए अतीत के नीति-नियंताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि उनके संगठन ने स्वदेशी मेधा, संसाधनों और ज्ञान पर कभी भरोसा नहीं किया तथा विदेशी पूंजी एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर अत्यधिक बल दिया। उन्होंने कहा कि '' हम स्थानीय मेधा, संसाधनों, ज्ञान, उद्यमिता और मानव मूल्यों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सभी देशभक्त नागरिकों एवं उद्योग से इस स्वदेशी स्वालंबन अभियान से उत्साह से जुड़ने का आह्वान करते हैं।उन्होंने लोकल वस्तु एवं फ़ूड प्रोडक्ट को अपनाने, अपने परिवार में संतुलित जीवन जीने एवं कम से कम खर्च के जीवन मूल्य विकशित करने के विषय पर जोर दिया ' समाज एवं सरकार के मदद से भारत में लोगों की भुखमरी से मौत नहीं हुई यह अन्य दुनिया की तुलना में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया कर्मठता की पराकाष्ठा और कौशल(क्राफ्ट) की पूंजी से ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा ।इसमें कोई दो राय नहीं कि संकट गहरा है, इंतजाम नाकाफी हैं, सेवाएं गुणवत्तापूर्ण नहीं है, रामराज्य अभी भी प्रतीक्षित ही है, ईमानदारी से कर्तव्य निर्वहन करने वालों की संख्या सीमित है। फिर भी हिंदुस्तान का हौसला टूटा नहीं है। हमारे किसानों के लाख संकटों के बाद भी भारत फिर उठ खड़ा होगा। कोरोना संकट के बाद का भारत एक नई तरह से सोचेगा, व्यवहार करेगा। साथ ही ज्यादा आत्मनिर्भर और ज्यादा समर्थ होगा।

फैंस के कोषाध्यक्ष रथिन भद्रा ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। कार्यक्रम में फैंस के राष्ट्रीय संगठन मंत्री गोलक बिहारी जी, बिहार व झारखण्ड के राष्ट्रीय सचिव डॉ अमर कुमार चौधरी, महासचिव साकेत मोदी, संयुक्त सचिव राजा बागची, सेल के एक्स एडिशनल डायरेक्टर डॉ हरिहरन, उत्तराखंड से प्रोफेसर डॉ राघवेंद्र कुमार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखण्ड के सहायक कुलसचिव डॉ शिवेंद्र प्रसाद, पूर्व न्यायाधिश रमेश कुमार मेरठिया, वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेन्द्र तिवारी, चिन्मय मिशन के ट्रस्टी श्री विनोद गढ़यान, श्री वेद प्रकाश बागला, श्री पवन मंत्री, श्री शशांक भारद्वाज एवं काफी संख्या में लोग मौजूद थे।

सिदो कान्हु मुर्मू वि.वि. में पांच जून को होगी राष्ट्रीय संगोष्ठी

संवाददाता

दुमका : विश्व पर्यावरण दिवस पर सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय संगोष्ठी (वेबिनार) का आयोजन 5 और 6 जून को किया गया है। संगोष्ठी का विषय 'जैव विविधता पर लॉकडाउन का प्रभाव' रखा गया है। इसमें देश के कई राज्यों से शोधार्थी एवं वैज्ञानिक अपनी बात ऑनलाइन रखेंगे। भाग लेने और शोध सार देने की अंतिम तारीख 3 जून निर्धारित की गई है। संगोष्ठी में भाग लेने के लिए किसी प्रकार की शुल्क नहीं रखी गई है।

विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित है संगोष्ठी

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉ अजय सिन्हा ने बताया कि इस वेबिनार को सफल बनाने के लिए आयोजन समिति का गठन किया गया है। इसके संरक्षक कुलपति प्रो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा और सह संरक्षक प्रति कुलपति प्रो हनुमान प्रसाद शर्मा हैं। वेबिनार के निदेशक एसपी कॉलेज के प्राचार्य डॉ संजय कुमार सिन्हा और विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ निलेश कुमार हैं। संयोजक बॉटनी के विभागाध्यक्ष डॉ एसएल बोंडिया और फिजिक्स के सहायक प्रोफेसर डॉ आरके यादव बनाये गये हैं।

कृषि पैकेज से किसानों को मिलेगा बेहतर मूल्य: नीति आयोग

एजेंसियां

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन सहित कृषि क्षेत्र के लिए जिन उपायों की घोषणा की है, उनसे किसानों को बेहतर मूल्य मिलने में मदद मिलेगी।

कृषि क्षेत्र के लिए 1.63 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कोविड-19 आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त का ब्योरा जारी करते हुए कृषि क्षेत्र के लिए कुल 1.63 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर करने के लिए कानून में संशोधन की भी घोषणा की।

आवश्यक वस्तु अधिनियम से होगा फायदा : इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को अपनी उपज बिक्री के लिए अपनी पसंद के बाजार में कहीं भी बेचने की सुविधा देने को भी एक नया कानून बनाया जाएगा। कुमार ने ट्वीट किया कि, 'वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन सहित किसानों के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की है। इससे किसानों को अधिक स्वायत्तता मिलेगी और उन्हें अपनी उपज के लिए आकर्षक मूल्य मिल सकेगा।

कृषि क्षेत्र के लिए शुरू होगा नया दौर: अमिताभ कान्त

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त ने भी कहा कि ये उपाय भारतीय किसान और कृषि क्षेत्र के लिए एक नया दौर शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि आवश्चक वसतु अधिनियम में संशोधन से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। उन्हें अपनी उपज को बेचने के लिए अधिक स्वायत्ता होगी।

कम रिस्क वाले क्षेत्रों में एहतियात के साथ आर्थिक गतिविधियां शुरू हों

राज्यों की सीमाओं पर प्रतिबंध से आर्थिक गतिविधियों में रूकावट : दीपक सूद

संवाददाता :राज्य की सीमाओं पर आवाजाही पर प्रतिबंध से आर्थिक गतिविधियों में बहुत सारी बाधायें आ रही ।ये बातें एसोचैम अध्यक्ष दीपक सूद ने कही। उन्होंने कहा कि उद्योग और व्यापार में धीरे-धीरे सुगमता लाने पर जोर दिया जाना चाहिये। यह सच है कि बड़ी संख्या में कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम को प्रमुखता से अपनाया है क्योंकि उन्हें कार्यालयों सरकारी संस्थानों में कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए न्यूनतम कर्मचारियों की आवश्यकता होती है ।लेकिन हरेक क्षेत्र में ऐसा संभव नहीं है। दुसरी बात कि लॉकडाउन 4.0 हममें अधिक आरामतलब की आदत भी डाल रही है। अब जबकि लॉकडाउन में हॉटस्पॉट और कंट्रोल जोन की अच्छी तरह से पहचान हो गई है तो हमें एहतियात के साथ कुछ व्यावहारिक छूट भी देनी चाहिये।

बिना रिस्क वाले क्षेत्रों में नियंत्रित छूट के साथ आर्थिक गतिविधियों को चालू करें। उन्होंने कहा जबकि नए केंद्रीय दिशानिर्देशों में निजी वाहनों को अनुमति दी गई है वहां भी राज्यों की सीमा पर आने जाने में कई बाधायें हैं दीपक सूद ने कहा कि नियमों का बहुत सख्ती से अनावश्यक उपयोग उद्योग धंधों पर प्रतिबंध लगा रहा है। अब एसोचैम सभी राज्यों से आर्थिक गतिविधियों को फिर से सुविधा में लाने के लिए आग्रह करेगा। दीपक सूद ने कहा कि केंद्र से यह भी आग्रह किया गया है कि वह राज्यों की सीमा पर होने वाली अड़चनों के समाधान के लिए कोई जरूरी कदम उठाये।

अम्फान तूफान से बंगाल को हुआ है सबसे ज्यादा नुकसान

एजेंसियां

अम्फान तूफान से बंगाल में खासा नुकसान हुआ है।अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान अम्फान में तेज हवा और भारी बारिश के कारण कच्चे मकान, बिजली के खंभे, पेड़ और ट्रैफिक सिग्नल उखड़ गए। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान ने सुंदरबन क्षेत्र में खासी तबाही मचाई। इसके अलावा दक्षिण और उत्तर 24 परगना, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, मिदनापुर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। ओडिशा के तटवर्ती इलाकों में तेज हवाओं और बारिश के कारण कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। तेज हवाओं के कारण दोनों ही राज्यों में हजारों पेड़ गिर गए हैं, संचार और बिजली सप्लाई भी प्रभावित हुईं। मुख्यमंत्री ममता ने कहा है कि उन्होंने इससे पहले ऐसी तबाही नहीं देखी है।

बांग्लादेश में भी अम्फान ने तबाही मचाई है। चक्रवात के कारण वहां कम से कम चार लोगों की मौत हो गई है। वहां कई जिलों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। बांग्लादेश में करीब 24 लाख लोगों को 15,000 से अधिक शिविरों में इस चक्रवात से सुरक्षित बचाने के लिए रखा गया है। बांग्लादेशी अधिकारियों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक बाढ़ संभावित द्वीप में रहने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों को भी शिविर में पहुंचा दिया गया है। अधिकारियों को डर है कि चक्रवात के कारण खड़ी फसल बर्बाद हो गई होगी और साथ ही उपजाऊ जमीन को भी नुकसान होने का अंदेशा है।

अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन शोध परियोजना की 50वीं राष्ट्रीय सोयाबीन समूह बैठक संपन्न

राजेश कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च (आईआईएसआर), इंदौर ने 21 मई को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर), नई दिल्ली के सौजन्य से संचालित अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन शोध परियोजना की 50वें राष्ट्रीय सोयाबीन समूह की बैठक की। इसमें सोयाबीन शोध परियोजनाओं से जुडे देश के 21 शोध केंद्रों के 80 वैज्ञानिकों ने जूम वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से भाग लिया।

इसके उदघाटन अवसर पर आईसीएआर महानिदेशक डॉ त्रिलोचन महापात्र ने कहा कि विश्व पटल पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सोयाबीन की खेती में भारत का चौथा स्थान है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन के आधार पर अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत आठवें स्थान पर है।

भारत में सोयाबीन की खेती विशेष रूप से महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में होती है। सोयाबीन में 38 -45 प्रतिशत प्रोटीन और 20 प्रतिशत तेल मौजूद होने के कारण इसे दलहनी एवं तेलहनी दोनों श्रेणी में रखा जाता है। परियोजना से जुड़े केंद्रों द्वारा सोयाबीन की अनेकों विशेष प्रजातियां विकसित की गयी है। इससे दलहनी/तेलहनी फसल में विशेष रूप से सोयाबीन का क्षेत्रफल और उत्पादन देश में काफी तीव्र गति से बढ़ने लगा है।

बैठक में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के आनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग में संचालित सोयाबीन परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने भी भाग लिया। परियोजना अन्वेषक डॉ नूतन वर्मा ने रांची केंद्र की शोध उपलब्धियों को रखा। उन्होंने बताया कि रांची केंद्र द्वारा सोयाबीन के दो किस्मों बिरसा सोयाबीन–1 और बिरसा सोयाबीन-2 विकसित की गयी है। इस वर्ष बिरसा सोयाबीन-3 किस्म को रिलीज किया जाना प्रस्तावित है। राज्य में इसकी व्यावसायिक खेती की व्यापक संभावना है। मार्केटिंग, प्रसंस्करण एवं मूल्यसंवर्धन व्यवस्था के आभाव में प्रदेश में इसकी खेती का विस्तार नहीं हो पाया है।

बैठक में शस्य वैज्ञानिक डॉ अरविंद कुमार ने प्रदेश में सोयाबीन की खेती के लिए यहां की जलवायु भी काफी उपयुक्त बताया।

औषधीय वनस्पतियों की खेती की झारखंड में असीम संभावनायें

डॉ कौशल कुमार

रोटी और बूटी : आजीविका एवं औषधीय पौध उत्पादन

झारखण्ड के वनों में बहुमूल्य औषधियाँ स्वभाविक रूप से पायी जाती है। प्रदेश की सखुआ के जंगलों में करीब 300 से भी अधिक लोक वानस्पतिक महत्त्व की प्रजातियाँ विद्यमान है। यहां के आदिवासी, ग्रामवासी एवं वनवासी अपनी परंपरागत चिकित्सा विधि में इसका प्रयोग सदियों से करते आ रहे है। आज हर्बल उत्पादों की पूरी दुनिया में मांग है। लेकिन अनुकूल परिस्थिति और पर्याप्त संसाधन मौजूद होने के बावजूद प्रदेश के किसान इस लाभ से वंचित है। औषधीय रूप में प्रयुक्त औषधीय उत्पाद का प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक विधि से व्यावसायिक खेती का किया जाना आवश्यक है। इसके बढ़ते महत्त्व को देखते हुए झारखण्ड में औषधीय पौधों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देकर प्रवासी और अप्रवासी लोगों के लिए रोजगार का सृजन तथा आजीविका का साधन स्थापित किया जा सकता है।

कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वानिकी संकाय के वनोत्पाद एवं उपयोगिता विभाग द्वारा किसानों को लगातार प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। इस दिशा में रांची के देवरी गांव में एलोवेरा विलेज भी स्थापित किया गया है। परन्तु किसानों को गुणवत्ता युक्त उन्नत किस्मों के औषधीय पौधों के जर्म प्लाज्म, जैविक खाद, मदर नर्सरी, सिंचाई की समुचित व्यवस्था, ग्रीन शेड नेट आदि जैसी सुविधा गरीबी के कारण आदिवासी, ग्रामवासी एवं वनवासी को उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस दिशा में राज्य सरकार के द्वारा खासकर कृषि विभाग के द्वारा उचित पहल करने की आवश्यकता है। राज्य में स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड भी मौजूद है। लेकिन अबतक इसकी उपयोगिता नहीं हो सकी है। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड द्वारा इस मद में काफी धन राशि मुहैया कराई जा रही है। लेकिन ठोस रणनीति एवं पहल के अभाव में कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, कृषि विभाग खासकर हर जिले के कृषि एवं उद्यान पदाधिकारीगण के विशेष तालमेल एवं समन्यवय द्वारा पहल किया जाना आवश्यक हो गया है। गंगा नदी कोरिडोर में औषधीय पौधों के उगाने के कार्य को नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड बढ़ावा दे रही है। ऐसे में अभी झारखण्ड की वैसी नदियां जो प्रदूषण से मुक्त है, खासकर दुमका जिले के टेपरा तथा मयूराक्षी नदी क्षेत्रों में भी कई वानस्पतिक औषधियां उगायी जा सकती है।

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वानिकी संकाय के वैसे वानिकी स्नातक, जो मेडिसिनल प्लांट विषय में प्रशिक्षित है तथा वी।वोक। इन हर्बल रिसोर्स टेकनोलोजी के छात्रों का रिसोर्स पर्सन्स के तौर पर उपयोग कर राज्य में बड़े पैमाने पर ग्रामीण स्तर तक किसानों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। झारखण्ड के किसानों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। राज्य सरकार द्वारा चिन्हित जिलों में औषधीय पौधों की प्रसंस्करण ईकाई एवं उत्पाद बनाने के सयंत्र की सुविधा को उपलब्ध कराकर आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है।

आज दुनिया भर में जैविक खेती से उत्पादित औषधीय उत्पाद की ही मांग है। राज्य में औषधीय पौधों में मण्डूकपर्णी, गिलोय, घृत कुमारी, अश्वगंधा, सर्पगंधा, सफ़ेद मूसली, केवोच, कालमेघ, वासा, मेंथा, शतावर, तुलसी, चित्रक, पिप्पली, गुड़मार, सदाबहार आदि के साथ –साथ नींबू घास, रूसा घास, खस आदि के व्यावसायिक खेती की व्यापक संभावना है। लंबी अवधि की औषधीय खेती में हर्रे, बहेड़ा, आँवला, लिसोढा, श्योनाक। पाटला, अर्जुन, भिलावा, कुटुज, मरोड़फली आदि वृक्षों को बढ़ावा दिया जा सकता है। कुजरी, लताकरंज, हड़जोड़ा को भी इसमें शामिल कर उगाया जा सकता है। इनके उत्पादों को झारखण्ड राज्य ब्रांड के नाम से स्थानीय और देश – विदेश के बाजारों में बिक्री कर किसानों की आमदनी और राजस्व को बढाया जा सकता है। इस दिशा में बहुराष्ट्रीय कंपनी के सहयोग से भी पहल की जा सकती है। कोरोना संकट ने राज्य को बहुत बड़ा अवसर उपलब्ध करा दिया। आज जरूरत है कि राज्य सरकार की ओर से इस ओर द्रुत गति से पहल हो। झारखण्ड को मेडिसिनल प्लांट रिसोर्स स्टेट के रूप में राष्ट्रीय एवं वैश्विक पटल पर स्थापित करने का प्रयास हो।

इस प्रयास में राज्य सरकार के उद्योग विभाग का भी सहयोग आवश्यक होगा। राज्य सरकार को औषधीय पौध के उत्पादन से आजीविका को 'रोटी और बूटी कार्यक्रम' के अंतर्गत बढ़ावा देने की जरूरत है। इस औषधीय उत्पादन को अच्छी कृषि और एकत्र के तरीके, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया तथा आयुष मंत्रालय के अनुरूप भी होना आवश्यक होगा। इस प्रयास में औषधीय उत्पादों की गुणवत्ता पर खास ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

लेखक वनोत्पाद एवं उपयोगिता विभाग, वानिकी संकाय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची में विभागाध्यक्ष हैं

फोटो न्यूज

सीएम आवास के पास चेतावनी दे रहा है पेड़

ये दोनो बड़े और सूखे पेड़ रांची आड़े हाउस के पास खड़े हैं। ये बार- बार जानलेवा होने की चेतावनी भी दे रहे हैं, लेकिन नगर निगम इसे अनसुना कर किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। इसके नीचे से होकर मुख्यमंत्री से लेकर सभी बड़े छोटे अधिकारी आते जाते हैं। इन दोनों पेड़ों की फुनगियों से होकर बिजली के तार भी गुजरते हैं। मॉनसून के चरम पर होने पर आंधी और तूफान में यह सूखे पेड़ कभी भी धराशायी हो सकते हैं और किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। आखिर नगर निगम इन्हें हटाने के बजाये किसी दुर्घटना का इंतजार क्यों कर रहा है?

फलों के राजा आम के अद्भूत रहस्य

ऋतु सिंह, योग प्रशिक्षक

आम जो फलों का राजा है विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन,कॉपर, पोटेशियम से भरपूर है।आम एक ऐसा फल है जिसके लिए हम पूरे साल इंतजार करते हैं ।जब ये कच्चा होता है तो विटामिन सी से भरपूर होता है और जब ये पक जाता है तो विटामिन ए से भरपूर होता है। भारत आम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है , आलफांसो सबसे उत्तम गुणवत्ता वाले आम है। कच्चे और पक्के आम दोनों के अपने अपने फायदे हैं। कच्चे आम का अचार, चटनी, पन्ना, मुरब्बा आदि बनता है और पक्के हुए आम का मिल्क सेक ,आम पापड़ आदि बना सकते है।

आम के फायदे

✓रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।
✓आम में विटामिन ए काफी होता है जो आंखों के लिए बहुत अच्छा है।
✓इसमें एंटी ऑक्सीडेंट कोलोन होता है जो कैंसर से बचाव में फायदेमंद है।
✓आम में इन्जाइम होते हैं जो पाचनशक्ति को अच्छा रखने के लिए सहायक होता है।
✓लौजी के रूप में खाएं जाने वाली कैरी आंतों के संक्रमण को कुदरती रूप से दूर कर लिवर को दुरुस्त करती है।
✓पेट सम्बंधित समस्याओं जैसे पेट में दर्द, बदहजमी,दस्त,उल्लिटयां में भी आराम मिलता है।
✓कच्चे आम का पन्ना पीने से गर्मी में लू से भी बचाव होता है।

आम खाने का सही तरीका

✓आम को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ मिलकर न खाए।
✓वर्कआउट से पहले आम खाना अच्छा है क्योंकि ये बेहतरीन एनर्जी बुस्टर है।
✓अपने नाश्ते या दोपहर के खाने से पहले आम खाना चाहिए रात में इसका सेवन न करें।
✓इसमे कोई और मिठी चिज़ मिला के न खाए क्योंकि आम पहले से नेचुरल सुगर काफी होता है ।माना आम सबका पसंदीदा फल है, फलों का राजा है लेकिन ज्यादा मात्रा में खाना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें कैलोरी भी काफी है। सही तरीके से और सही मात्रा में आम खाने से बहुत सारे फायदे हैं तो फिर सोच क्या रहे हैं ,मौसमी फल आम का जी भर कर आंनद लिजिए।

हमसे जुडे.रहने के लिए (इंस्टाग्राम) instagram पर फ़ॉलो करें। ritusinghfitness.

झारखंड के सुदूरवर्ती गांवों में आम जीवन जी रहे हैं लोग

देवाशीष

रांची : कोरोना महामारी से जहां सारे राज्य चिंतित और परेशान हैं वहीं झारखंड के सुदूरवर्ती गांवों में ग्रामीण आम जिंदगी जी रहे हैं। दरअसल इनकी दिनचर्या, वनों पर आश्रित होना, बाहरी लोगों से कम लगाव और उनकी आवाजाही न के बराबर होने के कारण आम दिनों की तरह ही है।

झारखंड को आंकड़ों में देखे तो करीब 79 लाख आबादी जिसका 80 फीसदी हिस्सा जंगलों में निवास करता है। झारखंड वन अधिकार मंच और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) हैदराबाद की एक अध्ययन रिपोर्ट कहती है कि झारखंड में कुल 32,112 गांवों में 14850 गांव जंगलों से लगे हैं। ग्रामीणों का 18,82,429 .02 हेक्टेयर वनभूमि पर वन अधिकार कानून के तहत सामुदायिक और व्यक्तिगत हक बनता है, जबकि एक करोड़ से भी अधिक आदिवासी व अन्य वन परंपरागत वन निवासी इसके लाभार्थी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चतरा लोकसभा में करीबन 13-14 लाख लोग वन अधिकार कानून के लाभार्थी हैं।''गांव के लोग जंगलों पर आश्रित पहले भी थे, आज भी हैं। इनकी 90 प्रतिशत जरूरतें गांव में पूरी हो जाती है, लॉक-डाउन के कारण बस जंगलों में उपजने वाली चीजों की बिक्री नहीं हो पा रही है, जिससे थोड़ी परेशानी हो रही है ।अभी यहां आर्थिक समस्या ज्यादा नहीं है। लोगों ने गेहूं काट लिया है। अभी कोरोना वायरस का वैसा भय नहीं हैं जैसा शहर में है। यहां के लोग घर और घर से खेत तक ही सीमित है। अभी तक इनका जीवन यापन इसी पर निर्भर है।

पौष्टिकता से भरपूर सुपर फ़ूड हैं मोटे अनाज

....पेज एक का शेष उपज 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त हुई है। राज्य के लिए विकसित रागी (मडुआ) की किस्में कृषि पारिस्थिकी के अनुकूल रागी (मडुआ) के प्रभेदों के मामले में प्रदेश समृद्ध है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अबतक अधिक उपज देने वाली 4 प्रभेदों को विकसित किया जा चुका है। वर्ष 1993 में रागी की ए। 404 किस्म विकसित की गई। 115-120 दिनों की अवधि वाली इस किस्म की औसत उपज 26-30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। वर्ष 1996 में बिरसा मडुआ -2 विकसित किया गया। 105-110 अवधि में परिपक्व होने वाली इस किस्म की औसत उपज 24-26 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। वर्ष 2015 में बिरसा मडुआ -3 विकसित किया गया। इसकी अवधि 110-115 दिन तथा औसत उपज 28-30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। वर्ष 2017 में सफ़ेद रागी किस्म जेडब्लूएम - 1 विकसित की गई। इसकी अवधि 105-110 दिन तथा औसत उपज 28-30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। रागी (मडुआ) के गुण रागी को भारतीय मूल का खाद्यान माना जाता है। यह उच्च पोषण मान वाला मोटा अनाज होता है, जिसमें 344 मिग्रा/100ग्राम कैल्शियम होता है। दूसरे किसी भी अनाज में कैल्शियम की इतनी अधिक मात्रा नहीं पाई जाती है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत रखने तथा मांसपेशियों को ताकतवर बनाने में मदद करता है। रागी में लौह तत्त्व की मात्रा 3 ।9 मिग्रा/100ग्राम होती है, जो रक्त का मुख्य घटक है। लौह तत्त्व की यह मात्रा बाजरे को छोड़कर सभी अनाजों से अधिक है। रागी (मडुआ) के पोष्टिक आहार रागी के आटे से हम रोटी, चिल्ला, इडली बना सकते हैं। रागी की खीर भी बनती है। छोटे बच्चों को (विशेषकर दो वर्ष से छोटे) पारंपरिक तौर पर रागी की लस्सी बनाकर खिलाई जाती है। रागी खाने की सलाह मधुमेह के रोगियों को दी जाती है। पारंपरिक रूप से रागी का इस्तेमाल खिचड़ी जैसे आहार के रूप में किया जाता है। अब बाजार में एक तुरंत प्रयोग योग्य आहार के रूप में रागी वर्मीसेली उपलब्ध है।

मोटे अनाज की खेती में समस्यायें

प्रदेश में उगाये जाने वाले मुख्य मोटे अनाज वाले फसलों रागी (मडुआ), जौ, ज्वार और बाजरा का उपयोग गरीबों द्वारा खाद्यान्न एवं पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। अन्य खाद्यान अनाज के मुकाबले मोटे अनाज का स्थानीय बाजारों में बाजार मूल्य काफी कम होता है। इसकी खेती से किसानों को विशेष आर्थिक लाभ नहीं होता, जो किसानों के विमुख होने की मुख्य वजह है। प्रदेश में मोटे अनाज के प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन ईकाई और बेहतर बाजार का अभाव है।

अब कागज़ की बोतल में मिलेंगे बियर और सॉफ़्टड्रिंक

डॉ. मोहन पहाड़ी

कोका और कार्ल्सबर्ग जैसी कंपनी ने प्लास्टिक को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। पर्यावरण के हित में फ़ैसला लेते हुए दोनों कंपनियों ने प्लास्टिक की बोतल उपयोग न करने का निर्णय लिया है। यानि दोनों ही कंपनियां ड्रिंक्स के लिये प्लास्टिक की बोतल की जगह प्लांट से बनाई गई बोतलों का उपयोग करेंगी।

रिपोर्ट के अनुसार, ये योजना **Renewable Chemicals Company Avantium** द्वारा तैयार की गई है। कंपनी बियर को स्टोर करने के लिये प्लास्टिक लेयरिंग के साथ अनोखा कार्डबोर्ड तैयार कर रही है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है कंपनी का दावा है कि ये प्लास्टिक सिंथेटिक प्लास्टिक नहीं है, ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। कंपनी का कहना है कि यूज़ होने के बाद इन बोतलों को आसानी से रिसाइकल कर लिया जाएगा। इसके साथ ही अगर इन्हें ज़मीन पर फेंका जाता है, तो ये कुछ टाइम में सड़ कर ख़ाद में बदल जाएंगी। कंपनी का कहना है कि कांच की बोतल, प्लास्टिक जितनी ख़तरनाक नहीं होती हैं, पर इन्हें रिसाइकल करना भी आसान नहीं होता है। इतनी ही नहीं, जंगल में सूर्य की रौशनी से टकराने पर कांच की बोतल से आग लगने की संभावना होती है। इसके साथ ही प्लास्टिक और कांच की बोतल जंगल से लेकर समुद्री जानवरों के लिये बड़ी परेशानी हैं। आंकड़ों के अनुसार, 300 मिलियन टन प्लास्टिक को जीवाश्म ईंधन से बनाया जाता है, जिसे सड़ने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। ख़ुशी हुई जानकर की बड़ी-बड़ी कंपनियां भी अब पर्यावरण को लेकर अब सजग हो रही हैं। यह छोटी सी पहल ज़िंदगी में बड़ा बादलाव ला सकती है।

लॉकडाउन से मत्स्य पालकों को हुआ भारी नुकसान

राजन कुमार

घर घर पोखर पान मखान
ये है मिथिला की पहचान

ये कहावत मिथिला के बारे में हैं जहां प्रत्येक घर का का अपना तालाब होता था और उसमें मखाने और मछली की उपलब्धता भी होती थी। खैर ये कहावत तो पुराने समय की बात है लेकिन वर्तमान में मछली के बाजार पर इस लॉकडाउन ने भी ग्रहण लगा दिया है।

मधुबनी जिले के ननौर गांव के रहने वाले विनीत मुखिया का पूरा परिवार मछली पालन करता है। वे लगभग 50 तालाबों में मछली पालते हैं। विनीत बताते हैं कि सामान्य स्थिति में जहां वे एक दिन में 100-150 किलोग्राम मछली तालाब से निकाला करते थे, लॉकडाउन के बाद महज 20 किलोग्राम ही निकालते हैं। कभी-कभी उसे भी बेचना मुश्किल पड़ जाता है। दरभंगा जिले के उपेंद्र सहनी की भी यही दशा है। वह कहते हैं कि जो मछली 200-250 रुपए प्रति किलोग्राम बिकती थी, आजकल 100 रुपए प्रति किलोग्राम से कम कीमत पर बेचनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी खरीददार नहीं मिल रहे।

भारत में लगभग 13 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक मछली उत्पादन होता है। यानी एक दिन में तकरीबन 35616 मीट्रिक टन उत्पादित होता है। लेकिन जबसे कोरोनावायरस संक्रमण भारत में पहुंचा और उसके बाद देश भर में लॉकडाउन लगा दिया गया, इससे मछली की बिक्री में तकरीबन 80 फीसदी की कमी आई है। हालांकि सरकार की तरफ से कुछ शर्तों के साथ मत्स्य उत्पादन क्षेत्र को लॉकडाउन से बाहर रखा गया। लेकिन मछली उत्पादन से जुड़े युवा कौशल बताते हैं कि लॉकडाउन से पहले ही यह अफवाह फैल गई थी कि मीट-मछली खाने से कोरोना होने की आशंका है। हालांकि सरकार ने इस तथ्य का खंडन भी किया। लेकिन लोगों ने मछली खरीदना कम कर दिया। अब चूंकि मछली मार्केट में भीड़भाड़ होती है, इसलिए सरकार ने मछली मार्केटों को भी बंद करा दिया था, लेकिन मछुआरे जो मछलियां नदी-तालाब से निकाल चुके थे और वे मार्केट तक भी नहीं पहुंची थीं, वे खराब हो गई। वैशाली के मछली पालक नरेश, जो कई सारे तालाबों से तक़रीबन 150-200 क्विंटल सालाना मछली उत्पादन करते हैं। वह कहते हैं, लॉकडाउन के कारण उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। मछलियां मार्केट तक नहीं पहुंच पा रही हैं। थोड़ा-बहुत छोटे-छोटे हाटों के माध्यम से बिक रही हैं, वह भी नुकसान के साथ। मछलियों को ज्यादा दिन तक तालाब में छोड़ भी नहीं सकते। इसलिए जो मछली 150-200 रुपए किलोग्राम के हिसाब से बेचते थे, उन्हें 30-40 रुपए में बेचना पड़ रहा हैं। चूंकि मौसम गर्म होने लगा है इसीलिए अधिक मछली तालाब में एक साथ नहीं रखी जा सकती है।

केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान के अनुसार, भारत में कुल मछली उत्पादन 2018-19 में लगभग 13.7 टन है, जिसमें से लगभग 35% का योगदान समुद्री क्षेत्र द्वारा किया जाता है। मछली पकड़ने के मौसम के दौरान मासिक औसत समुद्री मछली उत्पादन लगभग 0 .44 मिलियन टन आता है। सभी मैकेनाइज्ड सेक्टर और मोटराइज्ड सेक्टर में से आधे ने अपने ऑपरेशन को रोक दिया है, जिसके कारण औसत मासिक नुकसान 0 .395 टन प्रति टन है। औसत थोक मूल्य 175 रुपये प्रति किलोग्राम रखने से कुल घाटा लगभग 6,913 करोड़ रुपए हो सकता है। एक रिपोर्ट में कहा गया है, लॉकडाउन से देश में लगभग 224 करोड़ रुपए का दैनिक नुकसान हो रहा है। जबकि मासिक नुकसान 6,863 करोड़ रुपए बताया गया है।

गौरतलब है कि विश्व में मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश की जी.डी.पी. में मत्स्य पालन क्षेत्र 0 .91 फीसदी योगदान के साथ 1 .60 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत भी है।

हरे रंग की हुई अंटार्कटिका की सफेद बर्फ

एजेंसियां

- **अंटार्कटिका में सफेद से हरे रंग के हुए बर्फ के पहाड़, बदलाव देख वैज्ञानिक भी हुए हैरान**
- **अंटार्कटिका पर जलवायु परिवर्तन का असर**
- **अंटार्कटिका में सफेद पहाड़ हरे रंग के हुए**
- **वैज्ञानिकों ने बताया, शैवाल की वजह से ऐसा हो रहा है**

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा सकता है। अंटार्कटिका भी इससे अछूता नहीं है, वहां बर्फ से सफेद पहाड़ों ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। अंटार्कटिका में अब हरे रंग के बर्फ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। इन बर्फीले पहाड़ों ने तेजी से अपने रंग में बदलाव किया है।

अंटार्कटिका के सफेद बर्फ से लदे पहाड़ों को देखकर किसी का भी मन मंत्रमुग्ध हो जाएगा। लेकिन अब इन पहाड़ों द्वारा खुद को हरे रंग में तब्दील करने की प्रक्रिया हैरान करने वाली है। दुनियाभर के वैज्ञानिक इस असामान्य गतिविधि से चिंतित हैं।वैज्ञानिकों का कहना है कि पूरी दुनिया पर जलवायु परिवर्तन की मार पड़ रही है। इसका असर अंटार्कटिका पर भी देखा जा सकता है। अंटार्कटिका में पहाड़ों के रंग बदलने के पीछे की वजह पर्यावरण में आया बदलाव है। जलवायु परिवर्तन की वजह से बर्फ का रंग सफेद से हरा हो रहा है। इस बदलाव को इस तरह समझा जा सकता है कि अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों में भी इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

रंग बदलने के पीछे ये है वजह

वैज्ञानिकों ने पहाड़ों के सफेद से हरे रंग में बदलने की वजह शैवाल को बताया है। उनका कहना है कि अंट-र्कटिका में लंबे समय से शैवाल मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने कहा कि वहां शैवाल की मौजदूगी बढ़ गई है, जिस कारण पहाड़ों पर जमी बर्फ का रंग सफेद से बदलकर हरा होने लगा है। ब्रिटिश खोजकर्ता अर्नेस्ट शैकेलटन ने इस बारे में जानकारी दी है।

दो वर्षों के डाटा का विश्लेषण

यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सेंटीनल-2 सैटेलाइट के जरिए दो वर्षों का डाटा जमा किया है। इसमें अंटार्कटिका की सतह का सही तरीके से विश्लेषण किया गया। कैंब्रिज विवि और ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण ने साथ मिलकर एक मानचित्र तैयार किया है। इस मानचित्र में शैवाल के तेजी से बढ़ने का पता चलता है। खास तौर पर अंटार्कटिका पठारतट पर इसकी मात्रा ज्यादा पाई गई है। कार्बन का उत्सर्जन काफी बढ़ा है।

हरे रंग के साथ लाल और नारंगी रंग के भी शैवाल

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने बताया है कि वो इस बात की जांच कर रहे हैं कि शैवाल कहां से बढ़ रहे हैं और क्या भविष्य में इनके तेजी से बढ़ने की गुंजाइश है। शैवाल की खासियत होती है कि वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि इसका सीधा मतलब है कि इस इलाके में कार्बन का उत्सर्जन बढ़ा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस इलाके में यूके की पेट्रोल कारों के सफर की वजह से कार्बन का उत्सर्जन काफी बढ़ा है। वैज्ञानिक सिर्फ हरे रंग की नहीं बल्कि लाल और नारंगी रंग के शैवाल पर भी शोध कर रहे हैं। हालांकि ये शैवाल अंतरिक्ष से दिखाई नहीं देता है। ●

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

● **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक मनोरंजन सिंह द्वारा प्रकाशित तथा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित और सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2, टीवीएस गली, रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : JHAHIN/2019/78094, email:greenrevolt2019@gmail.com.☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।